सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 24 फाल्गुन, 1942 (श०)
15 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 08

(1)	गृह विभाग	03
(2)	वित्त विभाग	01
(3)	सामान्य प्रशासन विभाग	01
(4)	निर्वाचन विभाग	01
(5)	गन्ना उद्योग विभाग	01
(6)	उद्योग विभाग	01
	कुल योग --	08

एफ0 आई0 आर0 का अनुसंधान कराना

'क'-38. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "धान गेहूँ खरीद में 35 करोड़ का कैश क्रेडिट घोटाला" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सूबे में किसानों से धान और गेहूँ खरीद के लिये मिली सरकारी राशि में से राज्य के 13 जिलों के पैक्स एवं व्यापार मंडलों ने 35 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राशि वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2017-18 के बीच इन समितियों को दी गई थी, जबकि राशि नहीं लौटाने से संबंधित F.I.R. होने के बावजूद उनके खिलाफ अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जबकि सहकारिता निबंधक द्वारा पुलिस महानिदेशक से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह 8 वर्ष पूर्व ही किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संबंधित सभी F.I.R का अनुसंधान कबतक पूरा कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चुनावी खर्चों की जाँच

48. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 फरवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "टेंट-पंडाल लगा नहीं और 42 करोड़ का दे दिया बिल" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विधान सभा के चुनाव के लिये अधिग्रहण किये गये वाहनों के तेल मद में एक दोपहिया वाहन में सैकड़ों लीटर डीजल खर्च का बिल दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2014 में लोक सभा चुनाव के समय पटना जिले में 60 अर्द्धसैनिक बलों की कम्पनियों पर 30 लाख रुपये खर्च किया गया था जबकि 2020 में 215 कम्पनियों पर खर्च का आकलन 42 करोड़ दिखाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना जिला सहित राज्य के सभी जिलों की चुनावी खर्चों की जाँच करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

49. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य अपराध रिकार्डस ब्यूरो 2020 के आँकड़ों के मुताबिक राज्य में औसतन प्रतिदिन 9 हत्या, 6 लूट तथा 4 बलात्कार की घटनाएँ घटित हो रही है जिससे राज्य के नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल को चालू कराना

50. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-128 राघोपुर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 के बाद पटना जिला के बिहटा सहित राज्य के कई बंद हुई चीनी मिलों के चल-अचल परिसम्पत्तियों को सरकार द्वारा औने-पौने दामों पर बेच दी गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बेची गई बंद चीनी मिलों को निजी निवेशकों द्वारा चलाने की कोई कोशिश नहीं की गई और ना ही कोई अन्य उद्योग स्थापित किया गया तथा सरकार ने ऐसे निवेशकों पर कोई कार्रवाई भी नहीं की ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाने का विचार रखती है कि राज्य में उक्त बंद सभी चीनी मिलों की परिसम्पत्तियों की बिक्री से राज्य सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई तथा किसान हित में शेष बंद चीनी मिलों को कबतक चालू कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

51. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0ज0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम संयुक्त स्नातक स्तरीय पदों पर 2010 के विज्ञापन के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2012 में एवं मुख्य परीक्षा जनवरी, 2013 में आयोजित किया गया था लेकिन गलत प्रश्नों के कारण मामला उच्चतम न्यायालय तक गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्चतम न्यायालय ने एक कमिटी का गठन कर प्रश्नों में सुधार करते हुये मेधा सूची के अनुसार परिणाम प्रकाशित करने का आदेश 6 मई, 2020 को दिया था जिसके आलोक में आयोग द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 को किया गया तथा 394 सफल घोषित अभ्यर्थियों में से 191 अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से 20 अक्टूबर, 2020 तक किया गया किन्तु अबतक इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-दिनांक 8 मार्च, 2021 को सदन द्वारा स्थगित ।

बैंकों पर कार्रवाई करना

52. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "कोविड काल में भी बैंकों ने लोन न देने का बहाना बनाया" के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोविड महामारी में किसानों और खेती को नुकसान न पहुँचे इसके लिये सरकार ने राज्य में के0सी0सी0 सहित डेयरी, फिशरी और पॉल्ट्री एवं कृषि से जुड़े प्राथमिकता वाले लोगों को बैंक द्वारा 10 लाख 48 लोगों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, परन्तु 24 सितम्बर, 2020 तक मात्र 76 हजार 668 किसान आदि को ही लोन दिया गया है, जबकि किसानों की आय दोगुनी करने के लिये वार्षिक साख योजना में कृषि निवेश पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित विषय की जाँच कराकर लक्ष्य के अनुरूप ऋण नहीं देने वाले बैंकों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

53. श्री भुदेव चौधरी (क्षेत्र संख्या-160 धौरैया (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत रजौन एवं भोजपुर जिला सहित अन्य जिलों में बाबा साहब की मूर्ति पर कालिख पोतने हाथ-पाँव तोड़ने या मूर्ति को विखंडित होने की सूचना दी गयी है किन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा अबतक कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को संरक्षित करते हुये मूर्ति विखंडन कर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

54. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिल्क समग्र परियोजना (आई0एस0डी0एस0आई0) देश के दूसरे राज्य में लागू है परन्तु पूर्णियाँ सहित बिहार में लागू नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) पूर्णियाँ जो पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा एवं किशनगंज के लिये कार्य करते थे उक्त पद दो वर्षों से रिक्त रहने के कारण रेशम उद्योग के विकास का कार्य बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के लिये राज्य में सिल्क समग्र परियोजना (आई0एस0डी0एस0आई0) लागू करने के साथ सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । पूर्णियाँ सहित बिहार के अन्य जिलों में सिल्क समग्र परियोजना लागू है ।

(2) सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पूर्णियाँ का दो वर्षों से पद रिक्त है । परन्तु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ, सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पूर्णियाँ के अतिरिक्त प्रभार में हैं । कोशी प्रमंडल के पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार एवं किशनगंज में जीविका द्वारा कार्यान्वित मलवरी रेशम विकास योजना का अनुश्रवण उनके द्वारा किया जा रहा है ।

(3) सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के लिये राज्य में सिल्क समग्र परियोजना (आई0एस0डी0एस0आई0) के तहत दिनांक 19 फरवरी, 2021 को सम्पन्न हुये परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा पूर्णियाँ में 500 लाभुकों के लिये रुपये 19.64 लाख कटिहार में 200 लाभुकों के लिये रुपये 769.835 लाख एवं किशनगंज में 200 लाभुकों के लिये रुपये 769.835 लाख का योजना प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु को केन्द्रांश की राशि स्वीकृति हेतु भेजा गया है ।

उपर्युक्त खंडों से स्वतः स्पष्ट है, सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पूर्णियाँ का प्रभार महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ को दिया गया है । अतः यह पद रिक्त नहीं है तथा कार्य भी बाधित नहीं हो रहा है । फिर भी पदाधिकारी के उपलब्धता के आधार पर सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापन कर दिया जायेगा ।

पटना :
दिनांक 15 मार्च, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 129(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550